एमसीडी चुनाव: भाजपा 15 साल की 'उपलब्धियों' की अपेक्षा सतेन्द्र जैन को पकड़े हुए है

दिल्ली (म.मो.) दिल्ली नगर निगम का चुनाव पूरे जोर-शोर से चल रहा है। एक ओर आम आदमी पार्टी जहां भाजपा द्वारा बीते 15 साल में किये गये घोटालों एवं लूट-मार की कहानियां बताने के साथ-साथ अपने द्वारा किये गये कामों का विवरण पेश कर रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा सतेन्द्र जैन को भुनाने में लगी है।

सतेन्द्र जैन आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य एवं जेल विभाग के मंत्री हैं। इसके अलावा वे हिमाचल के चुनाव प्रभारी भी थे। हिमाचल में 'आप' की पकड़ एवं उनका चुनाव अभियान कमजोर करने की नीयत से मोदी के इशारे पर ईडी ने पैंतरा दिखाया तो 58 वर्षीय सतेन्द्र जैन बीते 6 माह से जेल में हैं। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सम्बन्धित कोर्ट ने ईडी से आवश्यक सबूत पेश करने के लिये अधिक जोर दिया तो ईडी ने उल्टे जज पर ही आरोप लगा कर उनके तबादले की ही मांग कर डाली।

अनेक रोगों से ग्रस्त बुजुर्ग जैन इलाज के लिये कई बार जेल से अस्पताल भी लाये गये थे। इस पर भी भाजपाईयों को बड़ी भारी तकलीफ़ होती थी। अब जेल में उनकी मालिश को लेकर भी भाजपाईयों के पेट में पूरे जोर का दर्द हो रहा है। यद्यपि जेलों के अंदर कैमरा अथवा किसी प्रकार का फोन ले जाने पर सख्त पाबंदी है, इसके बावजूद भाजपाईयों ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उनकी मालिश व खान-पान की वीडियोग्राफ़ी करके बिना मतलब का हंगामा बरपा रखा है।

इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया है कि बीमारी के चलते उन्हें फिजियोथरेपी दी जाती है। अगले ही दिन भाजपाईयों ने पता लगा लिया कि फिजियोथरेपिस्ट की बजाय दुष्कर्म का आरोपी उनकी मालिश कर रहा था। इसके अलावा वे घर का खाना फल, व सब्जियां तथा सूखे मेवे खा रहे हैं। भाजपाईयों को शायद यह मालूम नहीं कि जेल में मालिश कराना कोई गुनाह नहीं है। यदि किसी को फिजियोथरेपी की जरूरत भी होती है तो थरेपिस्ट कुछ देर के लिये थरेपी देकर मरीज के परिजनों को थरेपी देने का तरीका समझा कर चला जाता है। अब जेल में जैन के घरवाले तो आने से रहे, कैदी ही उनके परिजन हैं। कैदी द्वारा कैदी की मालिश करना कोई गुनाह नहीं है। इसके अलावा आज कल जेल की कैंटीनों से पैसे देकर शराब व मांस छोड़ कर खाने-पीने की वस्तुयें खरीदी जा सकती हैं।

भाजपाईयों को जेल में जैन तो नजर आ रहे हैं लेकिन केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री का बेटा एवं पांच किसानों का कातिल आशीष मिश्रा नजर नहीं आ रहा। जेल में उसके लिये एसी सहित तमाम सुविधाओं के अलावा घर से खाना, पीने के लिये शराब तथा चालीस पान नजर नहीं आते? गुजरात की बिलकिस बानो के 11 बलात्कारी एवं हत्यारे नजर नहीं आते जो दो-दो साल की पैरोल पर बाहर घूमते रहे और अंत में रिहा भी हो गये। सिरसा का बलात्कारी बाबा एवं हत्याओं में सजायाफ्ता रामरहीम की पैरोल भी नजर नहीं आती।

'हूडा' का ऑनलाइन सिस्टम फेल, ग्राहक परेशान

फरीदाबाद। हूडा विभाग की वेबसाइट पिछले 25 दिनों से बंद पड़ी है। जिससे लोगों का भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस विभाग में मुख्य प्रशासक कार्यालय के आईटी सेल द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशंस के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने एवं फैमिली आईडी से जोड़ने के लिए पिछले लगभग 20 दिन से सारे सिस्टम को ब्लॉक कर दिया गया है। जिसके कारण पूरे प्रदेश के सभी संपदा कार्यालयों में कोई भी प्लाट धारक अपने प्लाट के किसी भी कार्य से संबंधित ऑनलाइन आवेदन को करने के लिए असमर्थ हो चुका है।

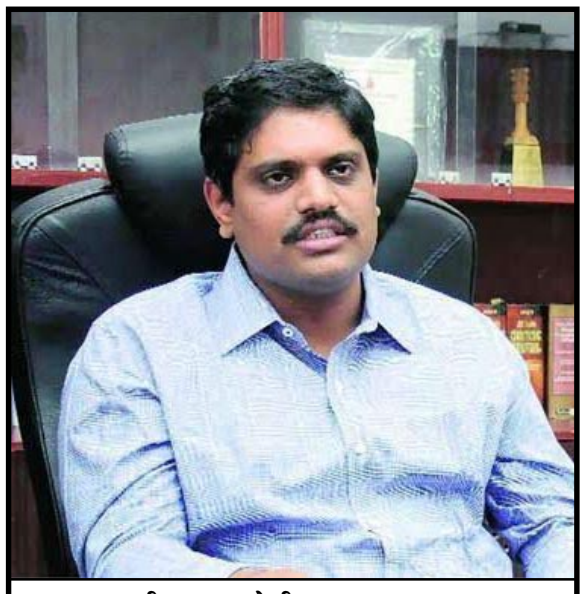

अजीत बाला जोशी, मुख्य प्रशासक हूडा

एनआरआई केस में प्लाट धारक अपनी संपत्ति का हस्तांतरण व अन्य कार्यों के लिए हवाई यात्रा का आने और जाने का टिकट पहले से ही बुक करवा कर आए हुए हैं।

विभाग की इस अदूरदर्शिता के कारण उन्हें लंबे समय तक इंतजार करने और कार्य में कुछ प्रगति ना होने के साथ-साथ इस विषय में किसी भी संबंधित अधिकारी द्वारा माकूल जवाब व आश्वासन ना दिए जाने के कारण मायूस होकर वापस लौटना पड़ा है। जबकि उनके बहुत से कार्य अपने अंतिम पड़ाव में थे। जिनके दस्तावेज जमा करवाना समयबद्ध सीमा में अति आवश्यक है। जैसे कि रि-अलॉटमेंट लेटर के दस्तावेज ट्रांसफर परमिशन जारी किए जाने के बाद समय पर जमा न करवाने पर पुन: प्रशासकीय शुल्क राशि सिस्टम के द्वारा मांगी जाती है।

यदि सिस्टम की अपनी खामियों या विभाग की लेटलतीफी और लापरवाही के कारण ऐसा हो रहा है तो, इसमें प्लाट धारकों का कोई दोष नहीं है।

इसलिए यह प्रशासकीय शुल्क राशि जो सिस्टम में मांगी जाती है। उसे ना लिया जाए और इसके साथ-साथ इसकी समय अवधि सीमा को 30 दिन के लिए और आगे बढ़ा दिया जाए। साथ ही साथ सभी तरह के अपडेशन और करेक्शन जिला स्तर पर किए जाने का प्रावधान भविष्य में अवश्य किया जाए।

कौआ चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। अभी तक हुड्डा के सारे काम बिना सॉफ्टवेयर के दफ्तर के बाबू किया करते थे। इस काम के बदले बाबू लोग अच्छी खास लूट कमाई करते रहे हैं। इसको रोकने के लिए सरकार ने जो सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑनलाइन प्रणाली विकसित करने का प्रयास किया था वह लगभग पूरी तरह से विफल हो रही है।

समझा जा रहा है कि जिस कम्पनी को सरकार ने इस काम का ठेका दिया था वह शायद इस काम के लायक ही नहीं है। किसी तरह जुगाड़बाजी लगाकर ठेका तो ले लिया लेकिन काम अधर में लटक गया। इसके चलते अब बाबुओं की बन आई है और ऑनलाइन की बजाये पुराने तरीके से ही काम को धक्का देने का प्रयास किया जा रहा है।

"तुम्हारी टांग जल गई, अब तुम अपने गाँव चले जाओ"

'घुट-घुट कर जीना, तिल-तिल मरना', फ़रीदाबाद के मज़दूरों का यही फ़साना

नरेश

फरीदाबाद के मजदूर बेहद बुरे हालात में अपने दिन गुजार रहे हैं. पहला उदाहरण, फरीदाबाद सेक्टर 24 स्थित, 'महामाया नामक ढलाई फैक्ट्री' (लोहा पिघलाने वाली फैक्ट्री) में काम करते हुए एक 40 वर्षीय मजदूर का पैर बुरी तरह जल गया. मजदूर का ईएसआईसी कार्ड नहीं था. इसलिए मजदूर मज़बूरी में झोलाछाप डॉक्टरों के पास अपना इलाज कराता रहा. मालिक की ओर से रोटी के लिए कोई पैसा नहीं, इलाज का पैसा नहीं. थोड़ा बहुत ठीक हो कर वह फिर फैक्ट्री पहुंचा और मालिक से काम करने की दरख्वास्त की. मजदूर फिर से काम करने लगा. दो-चार दिन ही बीते थे कि उसी मजदूर के आंखों में चोट लग गई. ईएसआईसी थी ही नहीं, कोई इलाज नहीं, बीमारी में ख़ाली बैठे दिनों को पैसा नहीं. मजदूर अपने परिवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में छोड़कर यहां अकेले रहता है. खाने को पैसा नहीं, कमरा किराया देने को पैसा नहीं, इलाज कराने को पैसा नहीं. मालिक से पैसा मांगा तो मालिक ने कह दिया, अभी तुम गांव चले जाओ. जब ठीक हो जाओ, तब आना. उसके बाद, जितने दिन तुमने काम किया है उसका पैसा दे दूंगा!!

दूसरा उदाहरण सेक्टर 24, फरीदाबाद के ही 'ओमेगा' नामक फैक्ट्री में लंबे समय से इलेक्ट्रिशियन का प्रस्तुत है. काम करते वक्त, एक मजदूर का बायां हाथ मशीन की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गया. ईएसआईसी कार्ड है, इसलिए ईएसआईसी में इलाज चल रहा है, मगर ईएसआई वाले कहते हैं, लंबा इलाज चलेगा. ईएसआईसी का डॉक्टर मेडिकल बना देता है. मजदूर ईएसआई के लोकल ऑफिस में मेडिकल जमा करने जाता है. वहां बैठा क्लर्क कहता है, जब फिटनेस हो जाए, तब सारे मेडिकल एक साथ जमा करा देना. मजदूर के पास खाना खाने के लिए, रोज ईएसआई आने जाने के लिए, गांव भेजने के लिए, कई बार बाहर से लिखी दवाइयां खरीदने के लिए पैसे ही नहीं हैं. मेडिकल के पैसे ईएसआई देगी तो सही, मगर कई महीनों के बाद. तब तक मजदूर कैसे जीवन चलाएं? इससे किसी को मतलब नहीं. फिटनेस मिलने के बाद, फैक्ट्री मालिक काम पर रखेगा या नहीं, इसका डर लगातार मजदूर को सतत सताता रहता है, क्योंकि हाथ खराब हो गया तो दूसरी जगह काम मिलना भी बड़ा मुश्किल है.

भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस सरकार के समय, सबसे अच्छे उद्योगपति का अवार्ड पाने वाले लखानी साहब, अपने मजदूरों का मजदूरी का पैसा, कई कई महीनों तक नहीं दे रहे हैं. मजदूरों की तनख्वाह से प्रोविडेंट फंड का कटा पैसा भी प्रोविडेंट फंड में जमा नहीं हो रहा है. ईएसआईसी के लिए काटा गया पैसा ईएसआईसी में नहीं जमा हो रहा है. वेलफेयर बोर्ड के नाम पर काटा गया पैसा वेलफेयर बोर्ड में नहीं जमा हो रहा है. मजदूरों से जबरन इस्तीफे ले लिए गए हैं, मगर उनका चुकता हिसाब किताब नहीं किया जा रहा है ग्रेटर फरीदाबाद में काम के दौरान एक नौजवान लड़की की मौत हो गई. लड़की का नाम मस्टररोल रजिस्टर में है ही नहीं. ईएसआईसी, पीएफ वेलफेयर बोर्ड में नाम है ही नहीं. स्वनाम धन्य सोशल मीडिया के स्टार

पत्रकारों ने यह खबर तो चलाई, मगर सिर्फ यह कहा कि लड़की को दुपट्टा ओढ़ कर मशीन पर काम नहीं करना चाहिए था. मशीन में दुपट्टा फंसने की वजह से ही उसकी जान चली गई. मथुरा रोड किनारे स्थित 'हरियाणा ग्लोबल' नामक फैक्ट्री में मजदूरों को जब-तब जबरन छुट्टी दे दी जाती है, और इन छुट्टियों का कोई पैसा नहीं दिया जाता. ऑर्डर कम होने की बात कही जाती है. फैक्ट्री के ज्यादातर मजदूर स्वयं काम छोड़कर दूसरी जगहों पर काम खोज रहे हैं, या काम कर रहे हैं. किए हुए काम का पैसा कब मिलेगा कोई पता नहीं है

ऐसा नहीं है कि मजदूरों के लिए कोई कानून नहीं है. मजदूरों के लिए ढेरों कानून है. हालांकि, नए लेबर कोड लागू होने के बाद, ये कानून भी बे-असर हो जाएंगे. मगर अभी, वह सभी पुराने कानून आज भी फरीदाबाद में बे-असर हैं. ऐसा भी नहीं है, कि फरीदाबाद में श्रम विभाग नहीं है, श्रम अधिकारी नहीं है, श्रम निरीक्षक नहीं है. सभी हैं, मगर मजदूर अपने अनुभव से यह जानते हैं कि ये सारे कोर्ट कचहरी, मजदूरों के हक में नहीं, पूंजीपतियों के हक में बनाए गए हैं. वहां जाने से पहले दलालों से, श्रम विभाग में केस डलवाने होंगे. दलाल, फाइल चार्ज के नाम पर 2000, 3000, 4000 मांगेंगे. उसके बाद कुछ मिला भी, तो उसमें से 15 प्रतिशत उन दलालों के हो जाएंगे. यह सब कितने समय में होगा, इसका कोई पता ही नहीं. तो मजदूर अपने हालात को, नियति मानकर सब कुछ बर्दाश्त किए चले जा रहे हैं.

पिछले दिनों बड़ी चर्चा रही, अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की. मगर फरीदाबाद की हजारों फैक्ट्रियों में धड़ल्ले से श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले एक भी पूंजीपति पर कोई बुलडोजर नहीं चला. ढेर सारे 'समाजसेवियों' का ध्यान फरीदाबाद में बीच सड़क पर बने मजार को हटाने पर लगा हुआ है, घुट-घुट कर जीते और तिल-तिल मरते मजदूरों की परवाह किसी को नहीं .